INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

Corporate Identity Number : L74899DL1984PLC019218
Regd Office : MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002
Phones: 41519433, 41520070 Fax : 41503479
Website : www.indialease.com E-mail : info@indialease.com
GSTIN : 07AAACI0149R1ZB

No. BSE/2022-2023/020

September 30, 2022

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Company Code: 500202

Re: Submission of newspapers publication (Annual General Meeting E-Voting Result)

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copy of Newspaper Publication of e-Voting Result of 37th Annual General Meeting in which all the 8 resolutions as stated out in the Notice of AGM dated August 10, 2022 were unanimously passed by the shareholders of the company, the said voting result were published in English & Hindi Newspaper editions respectively on 30th September, 2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For India Lease Development Limited

Rohit Madan
Manager, Company Secretary& CFO

Encl : As above

वार्डों के परिसीमन पर आप को भी ऐतराज

कांग्रेस के बाद सत्ताधारी पार्टी ने निगम की सीटों के कम होने पर चुनाव आयोग को सौंपी आपत्तियां

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

निगम परिसीमन समिति के चेयरमैन विजय देव को आपत्तियां देने के बाद आप विधायक दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज।

● कुछ वार्डों की आबादी 35 हजार तो कुछ की 93 हजार से अधिक : सौरभ

निगम वार्डों के परिसीमन को लेकर राजनीतिक दलों में भारी असंतोष है। प्रदेश कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने मौजूदा परिसीमन पर ऐतराज जताया है। दोनों पार्टियों ने परिसीमन मसौदा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 272 वार्डों की संख्या कम करके 250 वार्ड निर्धारित किए गए उसमें सिर्फ 22 विधानसभाओं में परिसीमन हो सकता था।

परंतु ड्राफ्ट परिसीमन को देखने के बाद सामने आया कि परिसीमन सभी 70 विधानसभाओं में मनमाने ढ़ंग से, बिना तर्क के पूरी तरह से भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसके कारण कुछ वार्डों की आबादी 35 हजार तो कुछ की 93 हजार से अधिक है।

राज्य चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विधायक को स्थानीय पदाधिकारियों के साथ परिसीमन मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा करने और अपनी टिप्पणियों और आपत्तियों को तैयार करने के लिए कहा है।

ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधि मंडल बृहस्पतिवार को वार्डों के परिसीमन के बारे में प्रारंभिक सुझाव और आपत्तियां परिसीमन आयोग को सौंपी है। इसके अनुसार वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 करने के एकल आदेश के साथ परिसीमन समिति का गठन किया गया था। समिति को 22 वार्डों को कम करने की आवश्यकता थी और इसका एकमात्र सही तरीका उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करना था, जिनमें 4 से 7 वार्ड थे। उस विधानसभा क्षेत्र के शेष वार्डों में वहां की आबादी को समान रूप से वितरित करके उनमें से प्रत्येक में 1 वार्ड कम करना था। इसका मतलब है कि यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में मूल रूप से 6 वार्ड थे तो समिति द्वारा इसे घटाकर 5 किया जाना चाहिए। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं, तो परिसीमन के बाद 3 वार्ड होने चाहिए। ऐसे में इन 22 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करने की जरूरत नहीं थी।

इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने निगम परिसीमन समिति के चैयरमेन विजय देव से मुलाकात कर दिल्ली नगर निगम के वार्ड परिसीमन पर अपनी पार्टी की ओर से आपत्ति और सुझाव दिए थे। कांग्रेस का कहना है कि निगम वार्ड परिसीमन अधिसूचना में प्रति वार्ड जनसंख्या औसतन 65 हजार तथा वार्ड में 10 प्रतिशत जनसंख्या कम या अधिक हो सकती है। स्पष्ट होने के बावजूद जब परिसीमन ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ तो उसमें 72 वार्ड ऐसे है जहां यह नियम लागू ही नहीं हुआ है। ड्राफ्ट में हैरानी की बात यह रही कि 32 वार्ड ऐसे बनाए गए हैं जिनकी जनसंख्या 80 हजार से अधिक है और 80 वार्डों में औसत जनसंख्या से 10 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या है। परिसीमन समिति ने सबसे कम जनसंख्या 35,509 का वार्ड किसी आधार पर बनाया है। यह समझ से परे है।

वायु प्रदूषण से निपटने की योजना कल से लागू होगी

● पंद्रह दिन पहले ही प्रतिबंधों को अमल में लाने से मिलेंगे बेहतर परिणाम : विशेषज्ञ

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बेहतर चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) को एक अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। पहले जीआरएपी को 15 अक्टूबर से अमल में लाया जाना था। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष अग्रिम कार्रवाई से गंभीर प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी।

जीआरएपी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हालात की गंभीरता के अनुरूप वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक समूह है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए जीआरएपी को अग्रिम तिथि से लागू करने का निर्णय लेने के वास्ते अगस्त 2021 में स्थापित वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जनता व विशेषज्ञों के उन सुझावों पर विचार किया है, जिसमें कहा गया है कि अग्रिम कार्रवाई से वायु गुणवत्ता को बेहद खराब होने से रोका जा सकता है।

इससे पहले, अधिकारी प्रदूषक तत्वों पीएम 2.5 और पीएम10 के एक विशेष सीमा को छूने के बाद ही उपायों को लागू करते थे। इस बार, प्रतिबंध पीएम2.5 और पीएम10 के स्तर के बजाय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की स्थिति पर आधारित होंगे।

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र में स्वच्छ वायु कार्यक्रम के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक विवेक चट्टोपाध्याय ने कहा कि हालात बिगड़ने से पहले उठाए गए रोकथाम संबंधी कदम से वायु गुणवत्ता को अचानक खराब होने से बचा जा सकता है, जब तक कि मौसम की परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल नहीं हों।

ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के विश्लेषक सुनील दहिया ने उम्मीद जताई कि अग्रिम कार्रवाई से वायु गुणवत्ता के बेहद खराब होने की घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान और सभी हितधारकों के साथ संवाद से ही पराली जलाने जैसी समस्याओं का समाधान होगा।

यौन उत्पीड़न के मामलो में एचआईवी जांच जरूर करें

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● डीसीडब्ल्यू ने कहा कि सभी मामलों में अस्पताल नही कर रहे हैं जांच, जिसके मद्देनजर दिया गया सुझाव

दिल्ली महिला आयोग ने यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों के पहली बार अस्पताल जाने पर उनकी अनिवार्य रूप से एचआईवी जांच करने का सुझाव दिया है। आयोग ने पाया है कि कई अस्पताल यौन उत्पीड़न के सभी मामलों में पीड़ितों की एचआईवी जांच नहीं कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर यह सुझाव दिया गया है।

डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एक नोटिस जारी कर पीड़ितों और अभियुक्तों की एचआईवी जांच किए जाने के मामलों की संख्या और पीड़ितों में एचआईवी के संचरण को रोकने के लिए अपनाए जा रहे कदमों व मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के बारे में जानकारी मांगी थी। आयोग ने कहा कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि कई अस्पताल यौन उत्पीड़न के मामलों में सभी पीड़ितों की एचआईवी जांच नहीं कर रहे। डीसीडब्ल्यू ने दीपचंद बंधु अस्पताल का हवाला दिया, जहां यौन उत्पीड़न के 180 मामलों में पीड़ितों की मेडिकल जांच तो की गई, लेकिन कुछ ही मामलों में एचआईवी जांच हुई।

आयोग ने कहा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पताल और राव तुलाराम अस्पताल ने बलात्कार पीड़ितों की एचआईवी जांच के संबंध में आंकड़े रखे ही नहीं। इसके अलावा, अस्पतालों ने अधिकांश पीड़ितों की अनुवर्ती एचआईवी जांच और परामर्श, जो तीन और छह महीने के बाद किया जाना चाहिए, उसके आंकड़े भी नहीं रखे। आयोग ने यह दावा भी किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राव तुला राम अस्पताल और जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ने कहा कि उनके पास पीड़ितों की अनुवर्ती जांच के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केवल दो अस्पतालों, आचार्य श्री भिक्षु राजकीय अस्पताल और पश्चिम जिले के गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल ने सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें आरोपी की एचआईवी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की है। आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार और पुलिस को यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की तत्काल निवारक देखभाल व एचआईवी का उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।

जलस्तर घटने के बावजूद, यमुना खतरे के निशान से ऊपर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● प्रभावित लोगों को अपने घरों में लौटने के लिए कुछ दिन और करना होगा इंतजार

यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है लेकिन यह अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। इसके चलते प्रभावित लोगों को नदी के तटीय निचले इलाकों में अपने-अपने घरों में लौटने के लिए कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी।

केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, यमुना में बुधवार को सुबह सात बजे जल स्तर 206.59 मीटर था जो बृहस्पतिवार सुबह नौ बजे तक घटकर 205.37 मीटर हो गया। बुधवार को दर्ज किया गया यमुना का जलस्तर अगस्त 2019 के बाद सबसे अधिक था। हालांकि, इसके दिन के दौरान खतरे के निशान 205.33 से नीचे आने की संभावना है। हालांकि यमुना के डूब क्षेत्र के लोगों को अभी कुछ दिन और ऊंचे स्थान पर रहना होगा।

दिल्ली प्रशासन ने मंगलवार को बाढ़ की चेतावनी जारी की थी, पुराने यमुना पुल पर रेल यातायात को निलंबित कर दिया था और यमुना के निकटवर्ती निचले इलाकों से लगभग 6,500 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया था, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदी में जलस्तर 206 मीटर के निशान को पार कर गया था। पिछले सप्ताह ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई।

पिछले तीन दिनों में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई है।

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से जल प्रवाह दर भी मंगलवार को सुबह सात बजे 96,000 क्यूसेक से घटकर बुधवार को सुबह नौ बजे 25,400 क्यूसेक और बृहस्पतिवार सुबह नौ बजे 17,800 क्यूसेक हो गई। एक क्यूसेक 28.32 लीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। हालांकि जलस्तर सामान्य होने में समय लगेगा।

दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली एनसीआर से विदा : आईएमडी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● दो से तीन अक्टूबर को इयान तूफान के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना

दक्षिण पश्चिम मानसून 19 प्रतिशत कम वर्षा के साथसाथ दिल्ल-एनसीआर से विदा ले लिया है। लेकिन इसके बाद भी राजधानी में वर्षा होगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह वर्षा भी लगातार कई दिन और अच्छे स्तर पर होगी इसकी वजह इयान तूफान है। स्काईमेट वेदर के अनुसार साउथ चाइना सी से उठा इयान तूफान दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रहा है। वैसे वियतनाम में आकर यह थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके अवशेष बंगाल की खाड़ी तक अपना असर दिखाएंगे।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार दो से तीन अक्टूबर के दौरान इस तूफान की वजह से ही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इससे फिर आगे भी कई वेदर सिस्टम विकसित होंगे। इस वजह से दिल्ली एनसीआर ही नहीं एमपी, यूपी और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून के दौरान अत्यधिक असमान वर्षा हुई है।

पीएफआई के तीन परिसरों को सील करने का आदेश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे तीन परिसरों को सील करने और उसके कोष के लेन देन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं।

जिन परिसरों को सील करने का आदेश दिया गया है, उनमें शाहीनबाग में रॉयल होटल के पास, एफ-30 बी,भूतल, जैद अपार्टमेंट, जामिया नगर के अबु फजल एन्क्लेव में भूतल, हिलाल हाउस और जामिया नगर के ठोकर संख्या सात में बी-27/2, तीसरी मंजिल शामिल है।

अगर 1 मिनट में 60 सीढ़ियां चढ़े तो आपका दिल दुरुस्त

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● अब तक लगभग 750 लोगों ने इस लक्ष्य को किया है पूरा

हृदय को दुरुस्त रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चलाए जा रहे एक अनोखे अभियान के तहत लोगों से एक मिनट में 60 सीढ़ियां चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने और पांच अन्य लोगों को टैग कर उन्हें यह चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हील फाउंडेशन के सहयोग से जेबी फार्मा हार्ट 2 हार्ट-हेल्दी हार्ट चैलेंज नाम का यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर को की गई थी।

आयोजकों के अनुसार, अब तक लगभग 750 लोग इस चुनौती को पूरा कर चुके हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डाले हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 सेकंड में चार मंजिल (60 सीढ़ियां) नहीं चढ़ पाना हृदय के सही से काम नहीं करने का संकेत हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक एक मिनट में 60 सीढ़ियां चढ़ सकने वाले लोगों का हृदय संभवत: श्रेष्ठ तरीके से काम कर रहा होता है। अभियान के तहत एक मिनट में 60 सीढ़ियां होंगी, जो चार मंजिल चढ़ने के समान है। इसके बाद वे इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करेंगे और पांच लोगों को टैग कर ऐसा करने की चुनौती देंगे।

सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. एस सी मनचंदा ने कहा कि हृदय रोग दुनियाभर में अब भी मौत का प्रमुख कारण बने हुए हैं। दिल संबंधी बीमारी से होने वाली 85 फीसदी मौतें हृदयघात और पक्षाघात के कारण होती हैं।

संस्कृत में खोज को आसान बनाने के लिए गूगल से समझौता

नई दिल्ली। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने इंटरनेट पर संस्कृत में खोज को आसान बनाने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। इसके तहत संस्कृत में आमतौर पर उपयोग होने वाली एक लाख पंक्तियां, उनके अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद के साथ उपलब्ध होंगी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आईसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे एवं गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए।

विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि आईसीसीआर और गूगल संस्कृत अनुवाद के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं और इससे गूगल को संस्कृत की सामग्री के विभिन्न भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमता या मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

सीता स्वयंवर में लक्ष्मण के तीखे वचन सुन क्रोधित हुए परशुराम

केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने विश्वामित्र के पात्र को किया जीवंत

लाल किला मैदान में आयोजित रामलीला में ऋषि विश्वामित्र की भूमिका में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्वनी चौबे।

● राम वनवास देख दर्शकों की आंखें हुई नम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

रामलीला मंचन के तीसरे दिन कलाकारों ने अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण-परशुराम संवाद के दृश्य प्रस्तुत किए। सीता स्वयंवर में पहुंचे कई राजा जब शिव का धनुष नहीं उठा सके तो जनक व्याकुल हो गए, तब भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष भंग किया।

लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला कमेटी में जनक दूत आगमन, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, रावण-बाणासुर संवाद, लक्ष्मण-परशुराम संवाद का मंचन हुआ खाद्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्वनी चौबे ने ऋषि विश्वामित्र की भूमिका निभाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

केंद्रीय मंत्री चौबे के अभिनय की सभी ने सराहना की। उनके संवाद बोलने पर खूब तालियां बजी। इस मौके पर चौबे ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर बिहार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते है। उनके तप-बल का ही प्रभाव था कि श्रीराम व लक्ष्मण ने, उनसे वीरोचित शिक्षा ग्रहण करके राक्षसी वृत्तियों का संहार किया था। उनका पात्र निभाना अद्भुत अनुभव भरा रहा।

महर्षि विश्वामित्र के पात्र निभाने का मकसद बक्सर की पौराणिक मान्यताओं से भी सभी को परिचित कराना था। बक्सर ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है। हजारों ऋषियों-मुनियों की तपोस्थली होने के कारण सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता था। भगवान राम ने ताड़का का वध यहीं किया था।

उधर आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेस-2 में दशरथ कैकई संवाद व राम बनवास कि लीला का मंचन निपुण कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कंप्यूटरराइड यंत्रों, लेजर लाइट व एलईडी स्क्रीन की मदद से सुंदरबन, भव्य एवं खूबसूरत महल दिखाया गया। राम बनवास गमन लीला का मंचन देख दर्शकों की आंखें नम हो गई।

Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Technology & Management
(Formerly Northern India Engineering College(NIEC))
Approved by AICTE & Affiliated to GGSIPU, Delhi
FC-26, Shastri Park, New Delhi – 110053.
Website: www.adgitmdelhi.ac.in

ADMISSION NOTICE
UNDER MANAGEMENT QUOTA for Academic Year 2022-23

B.Tech.(F/T - 4 Yrs.) & B.Tech. {2nd Yr.(LE) – F/T - 3 Yrs.}

Applications from Qualified candidates fulfilling the Educational Qualifications and eligibility criteria laid down in the "Admission Brochure for the Academic Session 2022-23" issued by Guru Gobind Singh Indraprastha University (GGSIPU), Delhi for "Management Quota" & respective guidelines of DTTE Govt. of NCT Delhi are invited for Admission under Management Quota under various categories of seats in the following Courses as prescribed by GGSIPU:

B.Tech. (1st Shift) (Course Code - 131)	B.Tech. (2nd Shift) (Course Code - 131)	B.Tech. (Lateral Entry) (Course Code - 128 & 129)
Computer Sc. & Engg.	Computer Sc. & Engg.	Computer Sc. & Engg.
Information Technology	Information Technology	Information Technology
Electronics & Communication Engg.	Electronics & Communication Engg.	Electronics & Communication Engg.
Civil Engineering		Civil Engineering
Mechanical Engineering		Artificial Intelligence & Data Science
Artificial Intelligence & Data Science		Artificial Intelligence & Machine Learning
Artificial Intelligence & Machine Learning		

Application Forms (hard-copy only)can be obtained from & submitted to the **Admission Cell** of the Institute during the working hours as notified by GGSIPU. The last date to fill up the management quota seats will be nine calendar days after the last date for regular admissions in the University announced by the GGSIPU for above Courses respectively. **Incomplete applications will not be considered. Admissions shall be on the basis of Merit. The Merit list of the Applicants will be displayed on the Website and Notice Board of the Institute within 2 days of closing date for submission of the application forms for respective courses.** Accordingly the 1st Round of Counseling at the Institute's Campus will be held within **3 days of drawing up of the Merit List of qualified management quota applicants.** The Candidates thus provisionally selected shall be required to complete all the Admission Formalities as per the rules & regulations laid down by GGSIPU in its Admission Brochure 2022-23. The 2nd Round of Counseling shall commence only after 12 hrs after provisional admission through 1st round of counseling.

Candidates must ensure to follow the latest COVID-19 guidelines issued by the Ministry of Health and Family Affairs, Govt of India during Counselling & Reporting at the Institute.

DIRECTOR

ILD

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड
सीआईएन नंबर : L74899DL1984PLC019218
जीएसटीआईएन : 07AAACI0149R1ZB
पंजीकरण कार्यालय: एमजीएफ हाउस, 4/17 बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली -110002
फोन : 011-41519433, 41520070 फैक्स : 41503479
वेबसाइट : http://www.indialease.com ई-मेल : info@indialease.com

37वीं वार्षिक आम बैठक का ई-वोटिंग परिणाम

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार और स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी ने 28 सितंबर, 2022 को वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए 10 अगस्त, 2022 के नोटिस में बताए गए सभी आठ प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) की प्रक्रिया का संचालन किया था। कंपनी ने 25 सितंबर, 2022 से 27 सितंबर, 2022 तक ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए 20 सितंबर, 2022 की कट ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सभी सदस्यों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की थी। कंपनी ने एजीएम के दौरान अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान की थी जो एजीएम से पहले अपना वोट नहीं डाल सकते थे। सुश्री अंजलि यादव, मैसर्स अंजलि यादव एंड एसोसिएट्स की प्रोपराइटर, (एफसीएस नंबर 6628, सीपी नंबर 7257) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया गया था और ई-वोटिंग परिणाम, उनकी रिपोर्ट दिनांक 29 सितंबर, 2022 के अनुसार इस प्रकार है :-

संकल्पों का विवरण	वोट किए गए सदस्यों की संख्या	कुल वैध वोट	कुल वोट अस्वीकृत	पक्ष में वोट		खिलाफ वोट	
				सं.	%	सं.	%
साधारण संकल्प संख्या 1 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन ऑडिटेड इंड-एएस वित्तीय विवरण प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।	180	180	0	94,28,811	100	100	0.00
साधारण संकल्प संख्या 2 श्री राजीव गुप्ता (डीआईएन: 00022964) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति की मांग करते हैं।	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
साधारण संकल्प संख्या 3 सुश्री सुमना वर्मा (डीआईएन:01448591) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति की मांग करती हैं।	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
साधारण संकल्प संख्या 4 मैसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की लगातार 5 (पांच) वर्षों की दूसरी अवधि के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में पुनर्नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक तय करना।	180	180	0	94,28,811	100	100	0.00
साधारण संकल्प संख्या . 5 कंपनी और मेसर्स द मोटर एंड जनरल फा. इनेंस लिमिटेड के बीच किए गए या किए जाने वाले सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन सहित संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी देना।	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
साधारण संकल्प संख्या . 6 कंपनी और मेसर्स राम प्रकाश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बीच किए जाने वाले सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन सहित संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी देना।	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
साधारण संकल्प संख्या 7 कंपनी और मेसर्स बाहुबली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच किए जाने वाले सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन सहित संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी देना।	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
विशेष संकल्प संख्या 8 बोनाफाइड और चैरिटेबल फंड में कंपनी का योगदान।	180	180	0	94,28,811	100	100	0.00

नोट: संबंधित पार्टियों को कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के क्रमश: संकल्प संख्या 2, 3, 5, 6 और 7 पर मतदान से दूर रखा गया है।

28 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक आम बैठक, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के आधार पर, बैठक के अध्यक्ष ने उपरोक्त परिणामों की घोषणा करते हुए कहा है कि 10 अगस्त, 2022 के नोटिस में निर्धारित संकल्प संख्या 1 से 8 तक को शेयरधारकों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम स्टॉक एक्सचेंज में जमा कर दिए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट www.indialease.com पर पोस्ट कर दिए गए हैं।

हेतु
इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड
हस्ता./-
रोहित मदान
प्रबंधक, कंपनी सचिव और सीएफओ
एसीएस - 13636

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 29 सितंबर, 2022

"India's Ties With China Built On Mutual Interest, Respect": S Jaishankar

WASHINGTON: (AGENCY)

External Affairs Minister S Jaishankar said on Wednesday that India will continue to maintain a relationship with China that is based on "mutual" sensitivity, respect and interest. S Jaishankar made the remarks while responding to a question on the consistent comments from Beijing about how things are "okay" between the two countries.

"What I have said, to my mind represents accurate policy assessment of where the state of our relations is. We continue to strive for a relationship with China, but one that is built on mutual sensitivity, mutual respect and mutual interest," S Jaishankar strongly asserted during a media briefing.

S Jaishankar, who is in the US to attend the recently concluded annual UN General Assembly, is now in Washington where he met his US counterpart, Antony Blinken and other top officials of the Biden Administration. Meanwhile, Chinese ambassador to India Sun Weidong stated that the situation on the India-China border is "overall stable" and the two sides have moved from the "emergency response" that followed the clash in Galwan Valley in June 2020 to "normalised management and control". "I think if the spokesperson of a foreign ministry were to say something, I would urge you to see a comment from the spokesperson of the Foreign Ministry of the corresponding country," S Jaishankar responded when asked for his reaction to Sun Weidong's comment. Just days before S Jaishankar hit out at China, without naming it, as he spoke at the United Nations Security Council (UNSC) session on Ukraine. In a reference to Beijing's decision to block the listing of terrorists, S Jaishankar said: "The fight against impunity is critical to the larger pursuit of securing peace and justice. The Security Council must send an unambiguous and unequivocal message on this count. Politics should never ever provide cover to evade accountability. Nor indeed to facilitate impunity. Regrettably, we have seen this of late in this very chamber, when it comes to sanctioning some of the world's most dreaded terrorists. If egregious attacks committed in broad daylight are left unpunished, this Council must reflect on the signals we are sending with impunity. There must be consistency if we are to ensure credibility." A day after his comment at UNSC, S Jaishankar and his Chinese counterpart Foreign Minister Wang Yi had a brief encounter when photos were taken at a BRICS gathering in New York last week and there was an awkward "unease." There were no bilateral meetings between the two foreign ministers. A similar awkward encounter was also visible when Prime Minister Modi stood beside Chinese President Xi Jinping during a group photo session at the recent Shanghai Cooperation Organisation summit.

3 More On Trial In Pakistan Anti-Terror Court For Blast Outside Hafiz Saeed's House

LAHORE: (AGENCY)

An anti-terrorism court in Pakistan has started the trial of three more suspects in a car bomb blast that killed three people outside the house of jailed terrorist leader Hafiz Saeed, considered the mastermind of the 2008 Mumbai attack. Saeed, chief of the banned Jamaat-ud-Dawah (JuD) has been serving jail sentence at the Kot Lakhpat Jail in Lahore for terror financing cases. There were unconfirmed reports that he was present at his house when the blast took place in June last year. "The prosecutors of the Counter Terrorism Department (CTD) of Punjab Police declared the suspects — Samiul Haq (mastermind) Aziz Akbar and Naveed Akhtar (facilitators) — guilty before the court," a CTD official told PTI on Thursday. He said the suspects, who were brought amid tight security, pleaded not guilty before the court. The official said the Anti-Terrorism Court (ATC) Lahore directed the prosecution to present witnesses before it on October 4. In January, the ATC had sentenced four suspects — Eid Gul (activist of banned Tahreek-e-Taliban Pakistan), Peter Paul David, Sajjad Shah and Ziaullah — to death on nine counts. The TTP's Eid Gul had installed explosives in the car used in the blast. The car belonged to Peter Paul David and other three — Sajjad Shah, Ziaullah and Ayesha — were facilitators.

court had also handed down five years' imprisonment to a woman, identified as Ayesha Bibi, during the in-camera trial proceedings at the high-security Kot Lakhpat Jail here. The prosecution had presented 56 witnesses against these five convicts. Three people were killed and over 20 others injured in the blast outside Saeed's Jauhar town residence here on June 23, 2021, that also damaged a number of houses, shops and vehicles in the area.According to the CTD,

Hafiz Saeed, the 71-year-old radical cleric and a UN-designated terrorist, whom the US has placed a USD 10 million bounty on, has been convicted for over 68 years' imprisonment in multiple terror financing cases moved by the ATC. His punishment is running concurrently.

Saeed-led JuD is the front organisation for the Lashkar-e-Taiba (LeT) which is responsible for carrying out the 2008 Mumbai attack that killed 166 people, including.

Kremlin Suspects Foreign "State Involvement" In Nord Stream Pipeline Leaks

MOSCOW: (AGENCY)

The Kremlin said Thursday that a foreign state was likely responsible for an incident that resulted in the leaks at the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines linking Russia to Europe. "It's very difficult to imagine that such a terrorist act could happen without the involvement of a state," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said in his daily press briefing.

After explosions were reported earlier this week in suspected sabotage, a fourth leak was detected in the undersea gas pipelines linking Russia to Europe on Thursday.

"This is an extremely dangerous situation that requires urgent investigation," Mr Peskov said.

On Wednesday, Russia launched an "international terrorism" probe.

Mr Peskov said such an investigation "required the cooperation of several countries" but denounced an "acute shortage of communications and unwillingness of many countries to contact" Russia.

Moscow said Wednesday US President Joe Biden was "obliged" to answer if Washington is behind the leaks.

Moscow and Washington both denied involvement in the incident.

The UN Security Council will meet on Friday to discuss the leaks. The Nord Stream 1 and 2 pipelines have been shrouded in political tensions since the Kremlin sent troops to Ukraine. Russia cut gas supplies to Europe in suspected retaliation against Western sanctions, but the pipelines still contained gas though they were not operational.

New Bill Seeks Green Card For Immigrants Living In US For Over 7 Years

WASHINGTON: (AGENCY)

A group of four top Democratic senators has introduced legislation to provide a much-needed pathway to a Green Card for up to 8 million people, including dreamers, H-1B and long-term visa holders. Under the bill, an immigrant may qualify for lawful permanent resident status if they have lived in the US continuously for at least seven years. The Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act was introduced in the Senate by Senator Alex Padilla and co-sponsored by Senators Elizabeth Warren, Ben Ray Lujan, and Senate Majority Whip Dick Durbin on Wednesday. "Our outdated immigration system is hurting countless people and holding back America's economy. My bill would update the Registry cutoff date for the first time in more than 35 years so that more immigrants can apply for legal permanent residence," said Padilla. "This could have a profound impact on millions of immigrants, some who have been living, working, and contributing to the United States for decades, by allowing them to live freely without the fear of an uncertain future," he said. A Green Card, known officially as a Permanent Resident Card, is a document issued to immigrants to the US as evidence that the bearer has been granted the privilege of residing permanently. The legislation would provide a much-needed pathway to a green card for up to 8 million people, including Dreamers, forcibly displaced citizens (TPS holders), children of long-term visa holders who face deportation, essential workers, and highly skilled members of the workforce such as H-1B visa holders who have been waiting years for a green card to become available, a statement said.

According to estimates by pro-immigration lobbying group FWD.us, if the undocumented individuals covered in this bill became citizens, they would contribute approximately $83 billion to the US economy annually and about $27 billion in taxes. Companion legislation has been introduced in the House of Representatives by Congresswoman Zoe Lofgren. "For decades, immigrants who contribute significantly to our communities and our economy have been relegated to a legal limbo," said Lofgren, Chair of the House Subcommittee on Immigration. "Updating this historically-bipartisan provision to provide lawful permanent resident status to immigrants who have been a part of our communities for years will make our immigration system fairer and our country stronger," she said. The lawmakers said Section 249 of the Immigration and Nationality Act, also known as the Registry, gives the Secretary of Homeland Security the discretion.

Nord Stream Gas Pipeline Leaks "Deliberate, Reckless, Sabotage": NATO

BRUSSELS : (AGENCY)

NATO on Thursday said leaks from the Nord Stream gas pipelines appeared to be sabotage and vowed a "determined response" to any attacks on their critical infrastructure. "All currently available information indicates that this is the result of deliberate, reckless and irresponsible acts of sabotage," the Western military alliance said in a statement. "These leaks are causing risks to shipping and substantial environmental damage. We support the investigations underway to determine the origin of the damage," it said. The statement said that the alliance was "committed to prepare for, deter and defend against the coercive use of energy and other hybrid tactics".

INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

CIN NO: L74899DL1984PLC019218
GSTIN : 07AAACI0149R1ZB
Regd Office :MGF House, 4/17 B, Asaf Ali Road , New Delhi -110002.
Phones :011-41519433, 41520070 Fax : 41503479
Website: http://www.indialease.com E-mail:info@indialease.com

E-VOTING RESULT OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to the provisions of Section 108 of The Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rule, 2014 and in compliance with Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 entered with Stock Exchange, the Company had conducted the process of electronic voting (e-Voting) on all the eight resolutions stated in the Notice dated August 10, 2022 for convening the Annual General Meeting on September 28, 2022. The Company had offered the e-voting facility through CDSL to all the Members of the Company as on the Cut Off date of September 20, 2022 to cast their vote electronically during the e-voting period from September 25, 2022 to September 27, 2022. The Company had also provided e-voting facility to its members during the AGM who could not caste their votes prior to AGM. Ms. Anjali Yadav, Proprietor of M/s Anjali Yadav & Associates, (FCS No. 6628, CP No. 7257) Practicing Company Secretaries had been appointed Scrutinizer and the e-voting results, as per her Report dated September 29, 2022 is as under:-

Particulars of the Resolutions	No. of Members Voted	Total Valid Votes	Total Votes Rejected	Votes in Favour		Votes Against	
				Nos.	%	Nos.	%
Ordinary Resolution No. 1 To receive, consider and adopt Standalone Audited Ind-AS Financial Statements of the company for the financial year ended March 31, 2022, the reports of the Board of Directors and Auditors thereon.	180	180	0	94,28,811	100	100	0.00
Ordinary Resolution No. 2 To appoint a Director in the place of Shri Rajiv Gupta (DIN: 00022964) who retires by rotation and being eligible, seeks re-appointment.	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
Ordinary Resolution No. 3 To appoint a Director in the place of Ms. Sumana Verma (DIN:01448591) who retires by rotation and being eligible, seeks re-appointment.	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
Ordinary Resolution No. 4 Re-appointment of M/s Jagdish Chand & Co. Chartered Accountants, as Statutory Auditors of the Company for a second term of consecutive 5 (Five) years and to fix their remuneration.	180	180	0	94,28,811	100	100	0.00
Ordinary Resolution No. 5 To approve the Related Party Transaction including Material Related Party Transactions entered into or to be entered into between the Company and M/s The Motor & General Finance Limited.	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
Ordinary Resolution No. 6 To approve the Related Party Transaction including Material Related Party Transactions to be entered into between the Company and M/s Ram Prakash & Company Private Limited.	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
Ordinary Resolution No. 7 To approve the Related Party Transaction including Material Related Party Transactions to be entered into between the Company and M/s Bahubali Services Private Limited.	174	174	0	7,73,270	99.99	100	0.01
Special Resolution No. 8 Company contribution to Bonafide and Charitable Funds.	180	180	0	94,28,811	100	100	0.00

Note : Related Parties are abstained from voting on Resolutions No. 2, 3, 5, 6 and 7 respectively of the Notice of the 37th Annual General Meeting of the Company.

The Annual General Meeting held on September 28, 2022 at New Delhi, the Chairperson of the Meeting, based on the Report of the Scrutinizer, declared the above results stating that resolutions Nos from 1 to 8 as set out in the Notice dated August 10, 2022 have been unanimously approved by the Shareholders. The Results of e-voting along with the Scrutinizer's Report has been submitted o the Stock Exchange and posted on the website of the company www.indialease.com.

For India Lease Development Limited
Sd/-
Rohit Madan
Manager, Company Secretary & CFO
ACS - 13636

Place: New Delhi
Date: September 29, 2022

MeToo Movement: Five Years On, How A Hashtag Shook The World

FRANCE: (AGENCY)

By forcing the world to wake up to the daily sexual abuse suffered by women, the #MeToo movement became a social revolution of historic importance. Its legacy is still being determined.

It began with a tweet: on October 15, 2017, US actor Alyssa Milano invited women to share their experiences of sexual harassment under the words "Me too".

Within a year, the hashtag had been used more than 19 million times, according to Pew Research Center - pushing the issue of sexual assault to the top of the global agenda.

Of course, the movement sat on the shoulders of decades of feminist struggle - even the phrase "Me Too" was a decade old, created by activist Tarana Burke for a charity aimed at survivors of abuse.

It caught fire in the wake of an explosive New York Times investigation about film producer Harvey Weinstein who, it transpired, had for years been raping and assaulting women, many in the industry, and getting away with it.

A reckoning came for many powerful figures in the entertainment industry. Kevin Spacey was dropped from "House of Cards" and Ridley Scott's "All the Money in the World" was reshot to replace him with another actor.

The heads of Amazon Studios, Fox News, CBS and Vox Media were forced out. Actor James Franco, opera singer Placido Domingo, comedian Louis C.K., fashion photographer Terry Richardson, celebrity chef Mario Batali - barely a week went by without another illustrious name being shamed.

The most serious allegations led to jail time for previously untouchable figures: Bill Cosby, once considered "America's dad", singer R. Kelly, and the ultra-connected financier Jeffrey Epstein. The pressure spread beyond the entertainment business to embroil politicians, sports stars and major tech firms such as Google and Uber.

Its strength lay in making visible what had always been lying in plain sight. "#MeToo showed that sexual and sexist violence was a daily reality, that it was banal," said Sandrine Ricci, a sociologist at the University of Quebec in Montreal. "The movement allowed people, especially victims, to better understand what was being done to them."

The epicentre was the United States, but the aftershocks were global. When abuse cases emerged, they were harder to ignore, whether it was a Serbian drama teacher accused of rape, abuse by ultra-Orthodox leaders in Israel, or a "sex for grades" scandal at a Moroccan university.

The Pew study found that a third of #MeToo tweets in the first year were written in a non-English language - seven percent were in Afrikaans, four percent in Somali - and that didn't count the regional variants, such as #YoTambien in Spanish or #BalanceTonPorc ("rat out your pig") in French. "People were surprised - they didn't know how common sexual harassment is," said Hillevi Ganetz at Stockholm University. "Day after day there were testimonies, it was overwhelming," she added. "It was a revolution and it was wonderful." The backlash was almost immediate. By its nature, #MeToo targeted behaviour that was often hard to prove in court, and led to accusations that people were being "cancelled" without a proper enquiry.

Some fretted that it spelled the end of flirting - that it could strip the tension out of sexual tension. French film icon Catherine Deneuve was one who spoke out against the movement's "puritanical" streak that threatened to turn women into "eternal victims".

The debate inevitably fell down the toilet bowl of the online culture wars - exemplified by the aggressive taking-of-sides in the Johnny Depp-Amber Heard trial earlier this year. The three-week disappearance of Chinese tennis star Peng Shuai after accusing former vice-premier Zhang Gaoli of forcing her into sex showed the serious extent that resistance could take.